www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

# देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 288 | जौनपुर मंगलवार, 09 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

## संक्षिप्त खबरें

### साकेत में इमारत गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के साकेत इलाके में इमारत गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल हुई है। अवैध निर्माण को लेकर एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में दिल्ली नगर निगम पर लगातार अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही बिल्डिंग कानूनों के उल्लंघन पर सख्त एक्शन की मांग की गई है।स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली में अवैध निर्माणों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई, भवन दुर्घटना की जवाबदेही तय करने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी का कहना है कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की लापरवाही की वजह से दिल्ली के साकेत इलाके में बिल्डिंग गिरी, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट में एमिकस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि दिल्ली की बाकी सभी इमारतों का भी संरचनात्मक ऑडिट कराया जाए। कोर्ट एमसीडी से जवाब–तलब करे कि यह अवैध इमारत इतने सालों तक कैसे बनती रही। जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पीड़ित परिवारों को मुआवजे और कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए।

### बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की पुनर्नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की पुनर्नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मुख्य सवाल यह उठाया गया है कि क्या कोई व्यक्ति, जो बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत दी गई छह माह की अवधि समाप्त होने के बाद पुनः मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर निरंतरता को असंवैधानिक बताते हुए उनकी नियुक्ति रद्द करने की मांग की है। याचिका में दलील दी गई है कि अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत गैर–विधायक को मंत्री बनाए जाने की छह महीने की संवैधानिक छूट केवल एक बार ही उपलब्ध है। इसका बार–बार इस्तेमाल इस्तीफा देकर, मंत्रिमंडल पुनर्गठन या पुनर्नियुक्ति के माध्यम से नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 164(4) का प्रावधान संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक जवाबदेही को दरकिनार करने के लिए नहीं है। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रावधान केवल अस्थायी व्यवस्था है, जिसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है । कि यह मामला केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति तक सीमित नहीं है ।

# गरीब कल्याण और मानव सशक्ति करण सरकार की प्राथमिकता रहे हैं - प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने अनेक परिवर्तनकारी बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीबों तथा वंचित वर्गों का कल्याण रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित होकर काम कर रही है और यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया गया है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जो लंबे समय तक मुख्यधारा के विकास से वंचित रहे हैं। अंत्योदय की भावना से संचालित रही विकास यात्रा प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना रहा है। उन्होंने कहा कि जन धन खाते, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी पहलों का लक्ष्य लोगों को गरिमा, सुरक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। जनकल्याणकारी योजनाओं से बढ़ी सामाजिक सुरक्षा नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इन पहलों के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग सुविधाएं, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। तकनीक बनी गरीबों के सशक्तिकरण का माध्यम पीएम मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि तकनीक के उपयोग से गड़बड़ियों में कमी आई है, प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है और शासन व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए शुरू की गई पहलें अब केवल सरकारी योजनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि मानव सशक्तिकरण का व्यापक अभियान बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह सामूहिक प्रयास विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में देश को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्टों की एक श्रृंखला में कहा कि पिछले 12 वर्षों में हुए बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा है। उन्होंने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसी सोच के साथ विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है।

## दिल्ली सरकार का जल्द को यमुना स्वच्छता अभियान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली सरकार यमुना नदी को उसका गौरव लौटाने, नदी के तटों को स्वच्छ बनाने व पर्यावरण संरक्षण के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि यमुना केवल नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है। यमुना के संरक्षण का दायित्व सरकार के साथ–साथ प्रत्येक नागरिक का भी है। इसी सोच को जन–जन तक पहुंचाने और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह व्यापक अभियान आयोजित किया जा रहा है। 14 जून को यमुना रिवरफ्रंट के प्रमुख घाटों पर एक साथ स्वच्छता और जन–जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। अभियान में लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ हजारों स्वयंसेवकों की भागीदारी होगी।

## केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के दहिसर में 'सुविधा केंद्र' का उद्घाटन किया

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के दहिसर क्षेत्र में एक नए 'सुविधा केंद्र' का उद्घाटन किया। यह केंद्र झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन से जुड़ी है, जिसमें हर नागरिक के जीवन को अधिक सुविधाजनक, सम्मानजनक और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चाहते हैं कि देश के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिलें, उनका जीवन आसान बने और समाज में उन्हें सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि शौचालय केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि लोगों की गरिमा और सम्मान से जुड़ा विषय है। इसी सोच के साथ स्वच्छता को देश के विकास की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग अपनी इच्छा से वहां नहीं रहते, बल्कि परिस्थितियों और मजबूरियों के कारण उन्हें ऐसे हालात में जीवन बिताना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि स्लम पुनर्विकास योजनाओं के माध्यम से हर झुग्गीवासी को पक्का और सम्मानजनक घर मिले। हालांकि जब तक यह लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं होता, तब तक लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में उत्तर मुंबई में एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है।

## जे.पी. नड्डा की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल और एनएचए के बीच होगा एमओयू

बंगाल, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम–जेएवाई) लागू करने वाला देश का 36वां राज्यध्केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है। इस संबंध में मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके साथ ही सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में भारत एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित समारोह में एबी पीएम–जेएवाई को पश्चिम बंगाल में लागू करने के लिए औपचारिक समझौता किया जाएगा। एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद राज्य के पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा। एमओयू हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा करेंगे। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के इस योजना में शामिल होने के साथ ही एबी पीएम–जेएवाई पूरे देश में लागू हो जाएगी। इसे देशभर के नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को सेकेंडरी और टर्शियरी स्तर की चिकित्सा सेवाओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाता है।

## अमित शाह करेंगे लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ, सीमा प्रबंधन में शुरू होगा डिजिटल युग

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार (9 जून, 2026) को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एलपीएमएस) का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। यह पहल स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाना है। इस अवसर पर अमित शाह डॉकी और श्रीमंतपुर भूमि बंदरगाहों पर नवनिर्मित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। एलपीएमएस का शुभारंभ भारत के सीमा प्रबंधन के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह प्रणाली व्यापार सुगमता, बेहतर कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ–साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सरकार की रणनीतिक सोच को भी दर्शाती है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे देश के सभी भूमि बंदरगाहों के परिचालन को एकीकृत प्रणाली में जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। यह लॉजिस्टिक्स और नियामकीय सूचनाओं के सुरक्षित तथा रियल–टाइम आदान–प्रदान को सक्षम बनाएगा, जिससे भूमि बंदरगाहों को हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों पर उपलब्ध आधुनिक डिजिटल प्रणालियों के समान सुविधाएं मिल सकेंगी। एलपीएमएस को एक न्यूट्रल और ओपन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। इसके माध्यम से सरकारी एजेंसियों, सीमा प्रबंधन से जुड़े विभागों और निजी ऑपरेटरों के बीच निर्बाध समन्वय स्थापित होगा। इससे प्रक्रियाओं में होने वाली देरी कम होगी और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। यह प्रणाली कार्गो और यात्रियों की प्रोसेसिंग के लिए एंड–टू–एंड डिजिटल वर्कफ्लो उपलब्ध कराएगी। इसमें स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल–विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। एलपीएमएस को आइसगेट (आईसीईगेट), यूएलआईपी और मोटर व्हीकल इकोसिस्टम जैसे प्रमुख राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्मों से भी जोड़ा गया है, जिससे सीमा प्रबंधन अधिक पारदर्शी, कुशल और इंटरऑपरेबल बन सकेगा।

## राष्ट्रीय राजनीति में दो ध्रुव स्पष्ट, विपक्षी दलों को साझा रणनीति पर आगे बढ़ना होगा : शरद पवार

नई दिल्ली , (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडियाश ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के अध्यक्ष शरद पवार ने विपक्षी एकता और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में इस समय दो स्पष्ट ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन है, जबकि दूसरी ओर उनकी विचारधारा से असहमत राजनीतिक दल और नेता एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि हाल ही में विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों के दौरान विपक्षी दलों ने अलग–अलग रणनीतियां अपनाईं। कुछ राज्यों में दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि कुछ स्थानों पर वे अलग–अलग मैदान में उतरे। वहीं, कुछ राज्यों में चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक समीकरणों में बदलाव भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों के बीच बेहतर समन्वय और संवाद की आवश्यकता है। पवार ने बताया कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके इस बैठक में शामिल नहीं हो रही है, लेकिन विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि अगले 8 से 15 दिनों के भीतर वरिष्ठ विपक्षी नेताओं की एक और बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें व्यापक स्तर पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय करने की कोशिश की जाएगी। एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख ने उम्मीद जताई कि विपक्षी दलों के बीच मौजूद मतभेदों का समाधान निकलेगा और सभी दल एक साझा राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी दल को अतिवादी या अत्यधिक कठोर रुख अपनाने से बचना चाहिए।

## आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है : संजय सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आआपा अब इंडी (आईएनडीआईए) गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आज होने वाली बैठक में आआपा शामिल नहीं होगी। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह सोमवार को एक बयान में इंडी ब्लॉक की बैठक पर कहा कि जहां तक पार्टी का सवाल है, पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आआपा इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसलिए बैठक में उसके शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान संजय सिंह ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि तमिलनाडु में बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच कांग्रेस द्वारा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) को विश्वास में लिए बिना अभिनेता विजय की पार्टी श्तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) को समर्थन देने के कारण दोनों दलों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि, संयुक्त रणनीति बनाने के लिए आज इंडी अलायंस की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। जिसमें विपक्ष की 23 पार्टियों के नेता शामिल होंगे।

## विकसित भारत 2047 के लिए जन भागीदारी, उद्यमशीलता और नवाचार जरूरी : ओम बिरला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जन भागीदारी, नवाचार, उद्यमशीलता और सामूहिक संकल्प के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। नई दिल्ली में आयोजित माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन में "माहेश्वरी समाज और विकसित भारत 2047" विषय पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उद्यमशीलता और राष्ट्र निर्माण दोनों को साथ–साथ आगे बढ़ाना होगा, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में समावेशी विकास, सामाजिक जिम्मेदारी और सक्रिय जन भागीदारी महत्वपूर्ण हैं। ओम बिरला ने माहेश्वरी समाज को देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की एक सशक्त शक्ति बताते हुए कहा कि इस समाज ने सेवाभाव, नैतिक व्यावसायिक मूल्यों, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि समाज ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जनसेवा और धर्मार्थ गतिविधियों के जरिए लगातार जनकल्याण का कार्य किया है। साथ ही पीढ़ी– दर–पीढ़ी विभिन्न क्षेत्रों में जनहित के लिए समर्पित संस्थानों की स्थापना कर समाज को नई दिशा दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि माहेश्वरी समाज ने समय और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महानगरों से

लेकर उत्तर–पूर्व और दक्षिण भारत तक समाज के लोगों ने अपनी उद्यमशीलता के बल पर नए अवसर पैदा किए, रोजगार सृजित किए और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, नैतिक आचरण और सामाजिक सद्भाव के प्रति समाज की प्रतिबद्धता ने व्यवसाय जगत में अनुकरणीय मानक स्थापित किए हैं। ओम बिरला ने कहा कि सफलता का वास्तविक पैमाना केवल धन अर्जित करना नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएशन और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। उन्होंने उद्यमी आनंद राठी की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी यात्रा युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी के योगदान की भी प्रशंसा की और कहा कि उनके प्रयासों ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा न्यायिक सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ऐसी हस्तियां समाज की उत्कृष्टता, नेतृत्व क्षमता और जनसेवा की परंपरा को दर्शाती हैं। भविष्य निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए।

# संपादकीय

## अंधकारमय सच्चाई उजागर

सिर्फ विजय या स्टालिन को ही दोष क्यों दिया जाए? किसी राज्य या यहां तक कि केंद्र के बजट पर गौर करें, तो यही कहानी घटित होती दिखती है। पैसा बांटो, वोट खरीदो– सबका मकसद है। तमिलनाडु की सत्ता संभालते ही सी. जोसेफ विजय ने वो रोना रो दिया, जो अब राज्यों में बनने वाली हर नई सरकार के मुखिया करते हैं! आरोप लगाया कि पूर्व डीएमके सरकार राजकोष को बदहाल छोड़ गई है, जिसका ब्योरा उनकी सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर देगी। कहा कि राज्य पर दस लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके बावजूद थलापति (कमांडर) पुकारे जाने वाले नए मुख्यमंत्री ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का एलान कर दिया। इससे हर साल 1,700 करोड़ रुपये से ज्यादा का नया बोझ राजकोष पर पड़ेगा। वैसे, यह सिर्फ झांकी है। वादों की अपनी लंबी लिस्ट को उन्होंने निभाया, तो उस पर सालाना एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च आएगा। 3. 31 लाख करोड़ रुपये के बजट वाले इस राज्य में फिलहाल 65 हजार करोड़ रुपये की वो कल्याण योजनाएं भी हैं, जिन्हें डीएमके सरकार ने शुरू किया था। जिस राज्य में राजस्व का 62 फीसदी हिस्सा तनख्वाह, पेंशन, और ब्याज चुकाने पर खर्च होता हो, वहां ऐसा जन कल्याण सिर्फ नया ऋण लेकर ही किया जा सकता है! हर कर्ज बुरा नहीं होता, बशर्ते उसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था एवं समाज की बुनियाद मजबूत करने के लिए किया जाए। इससे भविष्य में राजस्व बढ़ता है, जिससे विकसित समाज बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है। जबकि ऋण लेकर उपभोग में खर्च करना असल में भविष्य को दांव पर लगाना होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्टालिन हों या विजय, अथवा अन्य राजनीतिक दल एवं नेता– इस अनुभव सिद्ध तथ्य को नजरअंदाज किए रहते हैं। याद करने योग्य है कि 2021 में मुख्यमंत्री बनने पर डीएमके नेता एम.के. स्टालिन ने पूर्व एडीएमके सरकार पर खाली खजाना छोड़ जाने का आरोप लगाया था। मगर, नकदी ट्रांसफर की अपनी योजनाएं चलाने से वे बाज नहीं आए। वैसे सिर्फ उन्हें या विजय को ही दोष क्यों दिया जाए? किसी राज्य या यहां तक कि केंद्र के बजट पर गौर करें, तो यही कहानी घटित होती दिखती है। बुनियाद मजबूत करना आज किसी की प्राथमिकता नहीं है। पैसा बांटो, वोट खरीदो– सबका मकसद है। हर श्वेत पत्र इसी अंधकारमय सच्चाई को उजागर करता है।

## हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी का नया अध्याय

वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलते परिदृश्य के बीच भारत और नॉर्डिक देशों के संबंध नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ह्ल्यद्यश में आयोजित तृतीय भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने इस साझेदारी को हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास के व्यापक आयामों तक विस्तार देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह सम्मेलन केवल व्यापारिक सहयोग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक नीति, समुद्री अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, रक्षा उत्पादन और प्रतिभा गतिशीलता जैसे भविष्य–निर्धारक विषयों पर भी केंद्रित रहा। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग की शुरुआत वर्ष 2018 में पहले भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से हुई थी। तब से यह संबंध पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी में बदल चुका है। नॉर्डिक देशों की उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की विशाल बाजार क्षमता, युवा प्रतिभा तथा विनिर्माण शक्ति ने इस सहयोग को नई दिशा दी है। भारत की आर्कटिक नीति भी इस साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरी है। आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीय मानसून, कृषि, जल सुरक्षा और समुद्री तटीय क्षेत्रों पर पड़ सकता है। इसी कारण भारत ने अपनी आर्कटिक नीति भारत और आर्कटिकरू सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और वैश्विक सहयोग को प्राथमिकता दी है। नॉर्डिक देशों के साथ बढ़ता सहयोग इस नीति को व्यावहारिक आधार प्रदान करता है। व्यापार और निवेश में लगातार विस्तार नॉर्डिक देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। डेनमार्क के साथ भारत का वस्तु व्यापार 2025 में 2 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया, जबकि सेवाओं का व्यापार 4.25 अरब डॉलर तक पहुंचा। डेनमार्क की लगभग 200 कंपनियां भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट शहरी विकास और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। वहीं भारतीय कंपनियां भी आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही हैं। फिनलैंड के साथ तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग तेजी से बढ़ा है। फिनलैंड की 100 से अधिक कंपनियां भारत में कार्यरत हैं, जबकि भारतीय निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल तकनीक, 6जी अनुसंधान और स्टार्ट–अप सहयोग इस संबंध का प्रमुख आधार बन रहे हैं। आइसलैंड के साथ भारत ने भूतापीय ऊर्जा, मत्स्य पालन और आर्कटिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है। वहीं नॉर्वे के साथ समुद्री अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और आर्कटिक सहयोग को नई गति मिली है। नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 28 अरब डॉलर का निवेश इस बढ़ते भरोसे का प्रमाण है। स्वीडन के साथ भारत का व्यापार लगभग 7 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। स्वीडन की 280 से अधिक कंपनियां भारत में कार्यरत हैं, जबकि भारतीय कंपनियां भी वहां अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। रक्षा, दूरसंचार, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल तकनीक दोनों देशों के सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं। सॉफ्ट पावर बना संबंधों की मजबूती का आधार भारत और नॉर्डिक देशों के संबंध केवल आर्थिक और रणनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं। भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, संगीत, नृत्य और भारतीय त्योहारों ने नॉर्डिक समाज में विशेष स्थान बनाया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे के शहरों में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। नमस्ते स्टॉकहोम जैसे सांस्कृतिक आयोजन हजारों लोगों को आकर्षित करते हैं। इन देशों में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय ने भी दोनों क्षेत्रों के बीच मजबूत सांस्कृतिक पुल का कार्य किया है। स्वीडन में लगभग 88 हजार, फिनलैंड में 33 हजार और नॉर्वे में 30 हजार भारतीय समुदाय आर्थिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी तृतीय भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत–नॉर्डिक हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के रूप में सामने आया। इस पहल के तहत नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जल प्रबंधन, डिजिटल अवसंरचना, सतत विनिर्माण और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। यह साझेदारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, हरित रोजगार सृजित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अतिरिक्त जल प्रबंधन और संसाधन पुनर्चक्रण में नॉर्डिक विशेषज्ञता भारत के शहरी और औद्योगिक विकास को टिकाऊ बनाने में सहायक होगी। अनुसंधान, शिक्षा और तकनीकी सहयोग एसटीईएम शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार इस साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार हैं। भारत और नॉर्डिक देशों ने अगली पीढ़ी की संचार तकनीकों, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य–तकनीक और ध्रुवीय अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है।

# आखिर आर्थिक सुनामी के राजनीतिक व आर्थिक मायने मायने हैं

कमलेश

राहुल गांधी की ष्आर्थिक सुनामीष वाली चेतावनी को फिलहाल एक राजनीतिक चेतावनी और आर्थिक जोखिमों पर विपक्षी आक्रमण के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि उनका यह कहना कि भारत निश्चित रूप से आर्थिक सुनामी की ओर बढ़ रहा

है, अभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी होगी। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए इस बहस को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि भारत में वास्तव में ष्आर्थिक सुनामीष आएगी या नहीं, इसका कोई निश्चित उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हाल में दी गई चेतावनी ने आर्थिक और राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी का तर्क है कि वैश्विक संकट, विशेषकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, महंगाई, ईंधन कीमतों और आर्थिक असमानता के कारण भारत एक बड़े आर्थिक झटके की ओर बढ़ सकता है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था के पास पर्याप्त ष्शॉक एब्जॉर्बरष हैंकृविदेशी मुद्रा भंडार, नियंत्रित महंगाई, खाद्यान्न भंडार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और मजबूत कर–संग्रह जैसी व्यवस्थाएंकृजो बाहरी संकटों का सामना करने में सक्षम हैं। भारत के सामने कुछ वास्तविक चुनौतियाँ हैंरू जैसे वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि की आशंका। निर्यात और निवेश पर अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर। रोजगार सृजन की चुनौती। और कृषि और एमएसएमई क्षेत्र पर दबाव। लेकिन साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है, और कई आर्थिक संकेतक अभी व्यापक संकट की पुष्टि नहीं करते। जानकार बताते हैं कि आर्थिक सुनामी कोई औपचारिक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब अर्थव्यवस्था को अचानक और व्यापक झटका लगे तथा उसके प्रभाव दूरगामी हों। इसके कुछ संकेत हो सकते हैं– जीडीपी वृद्धि दर में तेज गिरावट। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। बैंकिंग या वित्तीय संकट। शेयर बाजार में भारी गिरावट। मुद्रा पर दबाव और महंगाई का बढ़ना। निवेश और उपभोग में तीव्र कमी। इतिहास में ळतमंज क्मचतमेपवद (1930 का दशक) और ळसवइंस थ्पदंदबपंस ब्तपेपे (2008) जैसी घटनाओं को आर्थिक सुनामी के उदाहरण माना जा सकता है। किसी भी सरकार या प्रधानमंत्री के रहते हुए आर्थिक संकट की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। अर्थव्यवस्था अनेक घरेलू और वैश्विक कारकों से प्रभावित होती है, जैसेकृवैश्विक मंदी या वित्तीय संकट। तेल की कीमतों में असाधारण वृद्धि। बड़े युद्ध या भू–राजनीतिक तनाव। प्राकृतिक आपदाएं या महामारी। घरेलू नीति संबंधी गंभीर त्रुटियां। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो बड़े झटकों को सहने में मदद करती हैंकृ जैसे– विशाल घरेलू बाजार। अपेक्षाकृत मजबूत बैंकिंग और नियामक व्यवस्था। बढ़ता डिजिटल भुगतान तंत्र। बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पर निवेश। विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर। दूसरी ओर, चुनौतियां भी मौजूद हैंकृजैसे– युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार सृजन। कृषि आय में सुधार। निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। और, आय असमानता और उपभोग मांग का प्रश्न। इसलिए निष्पक्ष रूप से कहा जाए तो ष्पीएम मोदी के रहते आर्थिक सुनामी निश्चित रूप से आएगीष या ष्कभी नहीं आएगीष्कृ दोनों दावे तथ्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं हैं। भारत की आर्थिक स्थिति कई संकेतकों पर अपेक्षाकृत मजबूत दिखती है, लेकिन किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह यह वैश्विक और घरेलू जोखिमों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। आर्थिक सुनामी की संभावना मुख्यतः नीतियों, वैश्विक परिस्थितियों और भविष्य की घटनाओं पर निर्भर करेगी, न कि केवल किसी एक नेता की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर। ष्आर्थिक सुनामीष एक रूपक (उमजंचीवत) है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यापक और तीव्र आर्थिक संकट जो समाज, बाजार, उद्योग, रोजगार और सरकार की वित्तीय स्थिति को एक साथ प्रभावित कर दे। जिस प्रकार समुद्री सुनामी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झकझोर देती है, उसी प्रकार आर्थिक सुनामी भी अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर गहरा असर डालती है। आइए जानते हैं आर्थिक सुनामी के प्रमुख संकेत के बारे में– पहला, शेयर बाजार में भारी गिरावट। दूसरा, निवेशकों की संपत्ति तेजी से घटती है। तीसरा, कंपनियों का बाजार मूल्य कम हो जाता है। चौथा, बेरोजगारी में तेज वृद्धि। पांचवां, उद्योगों और कंपनियों में छंटनी बढ़ती है। छठा, नए रोजगार सृजन की गति धीमी पड़ जाती है। सातवां, बैंकिंग और वित्तीय संकट। आठवां, ऋण वसूली की समस्या बढ़ती है। नौवां, बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर दबाव आता है। दसवां, मुद्रा और महंगाई पर असर। दसवां, राष्ट्रीय मुद्रा कमजोर हो सकती है। ग्यारहवां, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। बारहवां, व्यापार और उद्योग में मंदी। तेरहवां, उत्पादन घटता है। चौदहवां, निवेशक नए निवेश से बचते हैं। आर्थिक संकट केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि इसके राजनीतिक परिणाम भी होते हैंकृ पहला, सरकार की लोकप्रियता प्रभावित हो सकती है। दूसरा, विपक्ष को सरकार की नीतियों पर हमला करने का अवसर मिलता है। तीसरा, सामाजिक असंतोष और जनाक्रोश बढ़ सकता है। चौथा, चुनावी परिणामों पर असर पड़ सकता है। जहां तक भारत के संदर्भ में इसकी बात है तो भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में ष्आर्थिक सुनामीष का अर्थ होगाकृ विकास दर में तीव्र गिरावट, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, निवेश और उपभोग में कमी, राजकोषीय दबाव, तथा आम नागरिकों की क्रय शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव। हालांकि भारत की विशाल घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र, कृषि आधार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार जैसी ताकतें ऐसे संकटों के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकती हैं।

# पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश से रक्षा संबंध बना रहा तुर्किये

नीरज

दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीतिक बिसात पर अब एक नया और बेहद खतरनाक समीकरण तेजी से उभर रहा है। भारत विरोधी रवैये के लिए लंबे समय से चर्चित तुर्किये अब केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने बांग्लादेश के साथ भी अपने रक्षा और सामरिक रिश्तों को तेजी से विस्तार देना शुरू कर दिया है। ढाका पहुंचे तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने जिस तरह बांग्लादेश को दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया, उसने नई दिल्ली की चिंता और गहरा दी है। इस बयान को भारत के चारों ओर रणनीतिक दबाव बनाने की सुनियोजित चाल के रूप में देखा जा रहा है। तुर्किये ने साफ संकेत दे दिया है कि वह दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी केवल व्यापार या मानवीय सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहता। ढाका में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में रक्षा सहयोग, रक्षा उत्पादन, सामरिक साझेदारी और आर्थिक विस्तार पर जिस गंभीरता से चर्चा हुई, वह भारत के लिए साधारण घटना नहीं है। बांग्लादेश ने तुर्किये को रक्षा सामग्री निर्माण में निवेश का खुला न्योता दिया है। दोनों देशों ने पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है। यह वही तुर्किये है जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर वर्षों तक भारत विरोधी मोर्चेबंदी की, कश्मीर मुद्दे पर खुलकर इस्लामाबाद का साथ दिया और इस्लामी सहयोग संगठन के मंचों पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। उधर, दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता यह है कि तुर्किये अब भारत के पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान और पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश के साथ समानांतर सामरिक रिश्ते बना रहा है। यह दोतरफा दबाव की रणनीति जैसी दिखाई देती है। पाकिस्तान पहले से ही तुर्किये के रक्षा उद्योग, ड्रोन तकनीक और सैन्य प्रशिक्षण का लाभ उठा रहा है। अब यदि वही ढांचा बांग्लादेश तक पहुंचता है, तो भारत के लिए सुरक्षा समीकरण और जटिल हो जाएंगे। खास तौर पर तब, जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार अपनी विदेश नीति को नए ढंग से गढ़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा, तुर्किये और बांग्लादेश के बीच केवल रक्षा सहयोग ही नहीं, बल्कि आर्थिक और संस्थागत साझेदारी भी तेजी से बढ़ रही है। दोनों देश व्यापार को तेरह अरब डॉलर से बढ़ाकर बीस अरब डॉलर तक ले जाने की तैयारी में हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में तुर्किये को निवेश का निमंत्रण दिया गया है। वस्त्र, दवा निर्माण, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। ढाका में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अस्पताल और नर्सिंग संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। यह साफ दिखाता है कि तुर्किये केवल सैन्य साझेदारी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव स्थापित करने की नीति पर काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुर्किये दक्षिण एशिया में खुद को मुस्लिम दुनिया के प्रभावशाली संरक्षक के रूप में स्थापित करना चाहता है। रोहिंग्या मुद्दे पर उसकी सक्रियता, गाजा पर आक्रामक बयानबाजी और बांग्लादेश के साथ मानवीय सहयोग इसी रणनीति का हिस्सा हैं। लेकिन इसके पीछे छिपा बड़ा उद्देश्य क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार और भारत की सामरिक चुनौती को बढ़ाना है। वैसे तो तुर्किये लगातार यह कह रहा है कि भारत को उसके पाकिस्तान से रिश्तों की वजह से उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन असली सवाल भरोसे का है। राष्ट्रपति एर्दोआन कई बार खुलकर कश्मीर पर पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे चुके हैं। तुर्किये ने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा रिश्ते भी काफी मजबूत कर लिए हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्किये ने पाकिस्तान को रक्षा उपकरण और ड्रोन तक मुहैया कराए थे। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से आए जिन कई ड्रोनों को मार गिराया था, उनमें तुर्किये में बने ड्रोन भी शामिल थे। ऐसे में तुर्किये का भारत से दोस्ती और संतुलन की बात करना नई दिल्ली को एक सोची समझी रणनीतिक चाल जैसा लगता है। यही वजह है कि भारत भी अब तुर्किये को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। दरअसल, भारत ने हाल के वर्षों में साइप्रस और ऑर्मेनिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को तेजी से मजबूत किया है। ऑर्मेनिया अब भारतीय हथियारों का बड़ा खरीदार बन चुका है। साइप्रस के साथ भी भारत रणनीतिक और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। यह सीधे–सीधे तुर्किये को संदेश है कि यदि अंकारा भारत के पड़ोस में दखल बढ़ाएगा, तो नई दिल्ली भी तुर्किये के सामरिक क्षेत्र में जवाबी दबाव बनाएगी। जिस तरह तुर्किये पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह भारत भी तुर्किये के विरोधी या प्रतिस्पर्धी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। यह नई शीत प्रतिद्वंद्विता का संकेत है। उधर, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की विदेश नीति भी इस समय भारत के लिए गहरी चिंता का विषय बनती जा रही है। भारत की ओर से सबसे पहले आधिकारिक यात्रा का निमंत्रण मिलने के बावजूद रहमान ने पहले मलेशिया और फिर चीन जाने का फैसला किया। ढाका ने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि वह अब केवल भारत पर निर्भर रहने वाली नीति से आगे बढ़ना चाहता है। खास बात यह है कि चीन यात्रा के दौरान तीस्ता परियोजना समेत कई बड़े रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। साथ ही तारिक रहमान की मलेशिया यात्रा को केवल एक सामान्य विदेश दौरे के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसके पीछे साफ रणनीतिक सोच दिखाई दे रही है। बांग्लादेश नहीं चाहता था कि नई

सरकार की पहली विदेश यात्रा सीधे भारत या चीन में से किसी एक देश की तरफ झुकाव का संकेत दे। यही वजह है कि ढाका ने मलेशिया को पहले पड़ाव के तौर पर चुना, ताकि वह खुद को तटस्थ दिखा सके और भारत, चीन प्रतिस्पर्धा से दूरी बनाने का संदेश दे सके। लेकिन इसके राजनीतिक और सामरिक मायने काफी बड़े हैं। मलेशिया यात्रा के बाद चीन जाने की तैयारी यह संकेत देती है कि बांग्लादेश अब अपनी विदेश नीति को नए संतुलन के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। इससे भारत की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ढाका अब एक साथ चीन, तुर्किये, पाकिस्तान और अन्य इस्लामी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। यह आने वाले समय में भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक चुनौती को और कठिन बना सकता है। देखा जाये तो भारत के लिए यह समय बेहद सतर्क रहने का है। पाकिस्तान के साथ तुर्किये की साझेदारी पहले ही चिंता का कारण थी, लेकिन अब यदि बांग्लादेश भी उसी धुरी का हिस्सा बनने लगता है, तो यह भारत की पूर्वी सुरक्षा संरचना के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। हालांकि भारत को कम करके आंकना ढाका, इस्लामाबाद और अंकारा तीनों की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। भले ही बांग्लादेश चीन, पाकिस्तान और तुर्किये के साथ मिलकर नए समीकरण बनाने की कोशिश करे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति बेहद दूरदर्शी और बहुस्तरीय मानी जाती है। कभी कभार ऐसा लग सकता है कि भारत चुप क्यों है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सही समय आने पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब बेहद सटीक और ताकतवर होता है। कूटनीति का जवाब कूटनीति से और रणनीतिक चालों का जवाब उससे भी बड़ी चाल से देना ही मोदी की कार्यशैली रही है। यही वजह है कि आज भारत केवल अपने विरोधियों की गतिविधियों पर नजर नहीं रख रहा।

# एआई का जनजातीय भाषाओं में संवाद– समावेशी विकास का द्योतक

रंजना

हमारे देश भर में फैले जंगलों, पहाड़ियों और दूरदराज की बस्तियों में, एक शांत लेकिन सफल परिवर्तन चल रहा है। जनजातीय समुदाय लंबे समय से भारत की विकास गाथा के केंद्र में अपने उचित स्थान का इंतजार कर रहे थे। आज वे राष्ट्र

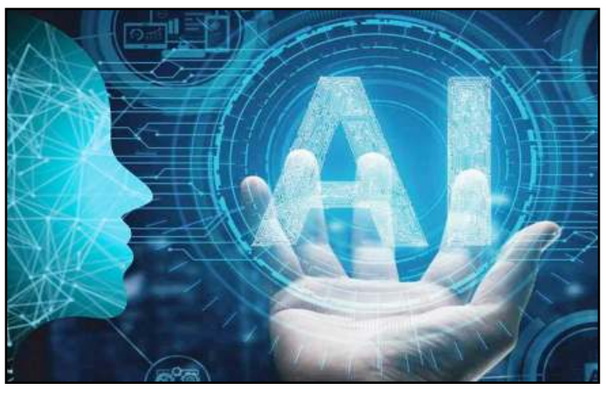

की प्रगति के सक्रिय वास्तुकार के रूप में उभर रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव की यही भावना हैरू विकसित भारत की यात्रा का एक राष्ट्रीय उत्सव, जहां प्रगति भूगोल या परिस्थिति का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का समान रूप से अधिकार है। महत्वाकांक्षा का पैमाना यह समझने के लिए कि प्रौद्योगिकी जनजातीय विकास के लिए अपरिहार्य क्यों हो गई है, किसी को पहले चुनौती की व्यापकता को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम–जनमन), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए), राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और संबंधित पहलों में 549 जिलों और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,911 ब्लॉकों के 63,000 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है, जिससे 5.5 करोड़ से अधिक आदिवासी नागरिक लाभान्वित हुए हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) पर विशेष ध्यान देने के साथ, इन प्रयासों का उद्देश्य आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसी आवश्यक सेवाओं का सम्पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है। इस तरह के विविध और विस्तृत इलाके में हर परिवार तक पहुंचने के लिए ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है जो डेटा–संचालित, कनेक्टेड और उत्तरदायी होती है और यही हम तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष जनजातीय गरिमा उत्सव का आयोजन लगभग चार विषयगत सप्ताह के आसपास किया जा रहा है, जो एक साथ जनजातीय विकास के पूर्ण आयाम को दर्शाते हैं। उद्घाटन का विषय, विकास के एक वाहक के रूप में प्रौद्योगिकी, इस बात को दर्शाता है कि कैसे डिजिटल सिस्टम, विज्ञान और नवाचार भारत के कुछ दूरस्थ समुदायों तक शासन और अवसर का विस्तार करने में मदद कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण के केंद्र में एक सरल सिद्धांत निहित हैरू जनजातीय भाषाओं, संस्कृतियों, विरासत और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का पर्याप्त सम्मान करते हुए विकास को अंतिम दूरी तक पहुंचना चाहिए। प्रौद्योगिकी द्वारा जनजातीय गरिमा को बढ़ावा उद्देश्य के साथ निर्देशित होने पर प्रौद्योगिकी क्या हासिल कर सकती है, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बिरसा 101 यानी सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी सीआरआईएसपीआर–आधारित जीन थेरेपी है। सिकल सेल रोग लंबे समय से जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य की एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है और भारत अब समानता और पहुंच में निहित उन्नत विज्ञान के साथ उस चुनौती का जवाब दे रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सीएसआईआर–इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी) और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अनुसंधान, नैदानिक परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। सीएसआईआर–आईजीआईबी में हाल ही में एक संगोष्ठी में वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और सिकल सेल योद्धाओं को एक साथ लाया गया, जो वैज्ञानिक प्रगति और प्रयासों के पीछे की मानवीय तात्कालिकता दोनों को दर्शाता है। साझा लक्ष्य स्पष्ट हैरू एक किफायती, एकमुश्त उपचारात्मक उपचार विकसित करना जो जरूरतमंद हर आदिवासी परिवार तक पहुंच सके। बीआईआरएसए 101 केवल चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि से भी बढ़कर है। यह एक घोषणा है कि भारत का सबसे उन्नत विज्ञान अपने सबसे पात्र समुदायों की सेवा करेगा। यह दृढ़ विश्वास एक पहल से कहीं अधिक गहरा है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) और आयुर्जेनोमिक्स जैसे प्रयास दर्शाते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक आदिवासी समुदायों द्वारा लंबे समय से संरक्षित समृद्ध औषधीय और पारिस्थितिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण, मान्यीकरण और संरक्षण में मदद कर सकती है। समावेशन की यही भावना इस बात को आकार दे रही है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जनजातीय विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में, मंत्रालय ने एक सरल लेकिन दृढ़ विश्वास पर आधारित एआई–सक्षम प्लेटफार्मों की श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भाषा एक बाधा नहीं है जिसे दूर किया जाना है, बल्कि एक पहचान है जिसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। आदि वाणी, जनजातीय भाषाओं के लिए एआई–संचालित अनुवादक, टेक्स्ट–टू–टेक्स्ट और टेक्स्ट– टू–स्पीच अनुवाद, ओसीआर और आदिवासी भाषाओं में सरकारी योजना की जानकारी के वितरण का समर्थन करता है, जिससे नागरिकों को घर पर बोलने वाली भाषा में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ने में सक्षम बनाया जाता है। ट्राइबॉट एक बहुभाषी संवादी एआई सहायक है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को तत्क्षण मार्गदर्शन और शिकायत निपटारे में सहायता प्रदान करके इस प्रयास को और मजबूत करता है। भगवान बिरसा मुंडा सेल और आईआईटी दिल्ली के साथ आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान भी इन प्रयासों पर चर्चा की गई, जो जनजातीय भाषाओं के दीर्घकालिक संरक्षण और सुदृढ़ीकरण सहित एआई के सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और समुदाय–केंद्रित इस्तेमाल पर केंद्रित थी। प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक अभिकथन और आर्थिक सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन रही है। आगामी ट्राइबएक्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जनजातीय कलाओं, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान, संगीत, शिल्प और सांस्कृतिक अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। इस प्रयास को पूरा करते हुए, जनजातीय भारत का प्रस्तावित जीआई संभावित कला और शिल्प एटलस भौगोलिक संकेत क्षमता के साथ जनजातीय हस्तशिल्प, वन उत्पादों और पारंपरिक कला रूपों का डिजिटल रूप से मानचित्रण करेगा, जिससे ब्रांडिंग, बाजार पहुंच और जनजातीय बौद्धिक विरासत की पहचान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पायलट आधार पर पांच राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में इनोवेशन हब की योजना बनाई गई है, जो नवाचार के नेतृत्व वाले आदिवासी उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए डिजाइन और उत्पाद विकास सहायता, जीआईएस–आधारित योजना डैशबोर्ड और इनक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर और आगे बढ़ेंगे।

## संक्षिप्त खबरें

### बंगाल में जनता ने लड़ा चुनाव, कुशासन से मिली मुक्ति : दिलीप

भदोही, (संवाददाता)। पश्चिम बंगाल के चापदानी के विधायक दिलीप सिंह मुन्ना ने कहा कि बंगाल में जनता ने चुनाव लड़ा। 70 साल के कुशासन से जनता को मुक्ति मिली। देश या विदेश कहीं भी रहूं। अपनी मिट्टी को नहीं भूल पाऊंगा। वह रविवार को अपने गृह जिले में पहुंचे तो बाबूसराय से लेकर कटका तक उनका गाजे–बाजे के साथ स्वागत किया गया। कटका में आवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बंगाल की वास्तविक स्थिति को बताया। बताया कि 22 साल तक कांग्रेस, 33 साल तक सीपीएम और 15 साल तक तृणमूल कांग्रेस के शासन से जनता त्रस्त हो गई थी। पूरे बंगाल में डर का वातावरण बना दिया गया था। प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। उद्योग, शिक्षा, सड़क, गरीबी, गुंडागर्दी से हर कोई परेशान था। वहां पर भाजपा ने नहीं बल्कि जनता ने चुनाव लड़ा। यही कारण था कि तृणमूल का सफाया हो गया और भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया।

### 20 पीएचसी पर लगेगी बॉयोमैट्रिक हाजिरी, रुकेगी मनमानी

भदोही, (संवाददाता)। जिले के 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी बायोमैट्रिक अटेंडेंस मशीनें लगाई जाएंगे। इससे डॉक्टरों और कर्मचारियों की लेटलतीफी पर अंकुश लगेगा। स्वास्थ्य विभाग इसकी कवायद में जुट गया है। अगस्त से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। जिले में तीन राजकीय जिला अस्पताल, छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। जिला अस्पताल और सीएचसी में यह व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन पीएचसी में अभी रजिस्टर पर ही हाजिरी लगाई जाती है। ऐसे में इन केंद्रों पर डॉक्टर और कर्मचारी समय से नहीं पहुंचते। कोई वाराणसी तो कोई प्रयागराज से ड्यूटी करने आता है। इसको लेकर शिकायतें भी मिलती रहती हैं। अधिकारियों के निरीक्षण में भी कई बार ऐसी मनमानी पकड़ी जा चुकी है। इसलिए सभी पीएचसी पर भी बायोमैट्रिक अटेंडेंस मशीन लगाई जाएगी। चकटोडर, हरिहरपुर, लालानगर, डेरवा, जयरामपुर, मानिकपुर, गिर्दबड़गांव सहित 20 पीएचसी पर रोज 1000 से 1200 मरीजों की ओपीडी होती है।

### कारपेट इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल में बनाएं भविष्य

भदोही, (संवाददाता)। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) ने एक ऐसा अल्प अवधि का पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसकी मांग देश और विदेश दोनों जगह है। कारपेट इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल नामक यह कोर्स चार महीने का होगा। आठ जून से यह शुरू हो रहा है। इसमें दाखिला लेकर युवा अपना हुनर निखार सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। संस्थान के निदेशक प्रो. राजीव कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि इंडस्ट्री की ओर से इसकी मांग आने के बाद गंभीरता से विचार कर पाठ्यक्रम तैयार किया गया। बताया कि संस्थान में कालीन एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी में चार वर्षीय बीटेक कोर्स चल रहा है, जिसकी पढ़ाई कर सैकड़ों युवा देश–विदेश के अच्छे संस्थानों में कार्यरत हैं। बताया कि कालीन उद्योग में डाइंग (रंगाई), कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग से जुड़े चार और छह महीने के कोर्स पहले से संचालित किए जा रहे हैं। इनका प्रशिक्षण हासिल कर युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। नए कोर्स के बारे में उन्होंने बताया कि आज के दौर में भारी संख्या में कालीन निर्यातक, कालीन आयातक और आयातकों के एजेंट भारत में भी और विदेश में कारपेट इंस्पेक्शन व क्वालिटी कंट्रोल के लिए युवाओं की भर्ती कर रहे हैं। इनका काम होता है कि वे कालीनों की गुणवत्ता जांच सकें। वर्तमान में कालीन उद्योग में ऐसे युवाओं की कमी है। कालीन निर्यातकों की ओर से इस ओर ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद चार महीने का कोर्स तैयार किया गया है। कोर्स की फीस 20 हजार रुपये रखी गई है। प्रतिदिन दो घंटे की कक्षाएं लेकर युवा अपना कौशल विकास कर सकते हैं। इसमें कालीन बुनाई, धुलाई, स्ट्रेचिंग से लेकर पैकिंग तक की जानकारी दी जाएगी।

### उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने राजीव मोदनवाल

भदोही, (संवाददाता)। नगर के वार्ड संख्या नौ स्थित बीडी कारपेट परिसर में रविवार को उद्योग व्यापार मंडल की बैठक हुई। इसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से राजीव मोदनवाल को अंगवस्त्रम भेंट कर नई बाजार उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में स्वाभिमान मोदनवाल, नारायण मोदनवाल, सुरेश साहू एवं उमेश विश्वकर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया। रमेश जायसवाल और अमित बरनवाल को महामंत्री, रजत सेठ, बद्री चौहान, शीतला प्रसाद उमर, धीरज साहू एवं निखिल बरनवाल को मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी तरह गोपाल उमर एवं बबलू खान को कोषाध्यक्ष जबकि नीरज जायसवाल और जयकुमार मोदनवाल को मीडिया प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा विनोद शर्मा, ओमकारनाथ मोदनवाल, मनमोहन मोदनवाल एवं मंटू जायसवाल को संरक्षक तथा ताराशंकर मोदनवाल, अनिल मोदनवाल, विनोद मोदनवाल, धर्मेंद्र उमर, लल्लू शर्मा एवं सरफराज आलम को सदस्य नामित किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव मोदनवाल ने व्यापारियों के हितों की रक्षा एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। इस दौरान जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता एवं जिला महामंत्री विनय कुमार मौजूद थे।

### शिवाला फिश मार्केट की तर्ज पर शिफ्ट होंगी मांस–मछली की दुकानें

वाराणसी, (संवाददाता)। वाराणसी शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और बेहतर यातायात व्यवस्था वाला बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम की योजना के तहत शहर की सीमा के भीतर संचालित मांस और मछली की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से शहर के बाहर विकसित किए जाने वाले विशेष बाजारों में स्थानांतरित किया जाएगा। इन कारोबारियों को शिवाला स्थित फिश मार्केट की तर्ज पर विकसित आधुनिक बाजारों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, सदन से प्रस्ताव पारित होने के बाद पांच स्थानों पर जमीन चिह्नित कर ली गई है। इनमें रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर क्षेत्र शामिल हैं। इन स्थानों पर आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक बाजार विकसित किए जाएंगे। इसके बाद शहर के भीतर संचालित मांस और मछली की दुकानों को वहां स्थानांतरित किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इन प्रस्तावित बाजारों की ड्राइंग और डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

## मृत्युंजय महादेव धाम में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में बक्शा विकास खंड के उमरक्षा गांव स्थित मृत्युंजय महादेव धाम पर आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। गाजे–बाजे और धार्मिक जयघोषों के बीच निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश यात्रा यज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर गांव का भ्रमण करते हुए हनुमान मंदिर के रास्ते सई नदी तट पहुंची। वहां मुख्य यजमान सहित 101 महिलाओं ने विधि–विधान से कलश में जल भरा और पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता की। यात्रा के दौरान महिलाएं भक्ति गीत गाती रहीं, जबकि युवक जयकारों के साथ नृत्य करते हुए आगे बढ़े। पूरे मार्ग में वातावरण भक्तिमय बना रहा। यज्ञाचार्य एवं कथा व्यास पंडित अनिलेश शुक्ल महाराज ने बताया कि विद्वान ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वेदी निर्माण, पूजन और कथा महात्म्य का आयोजन किया गया। सायंकालीन कथा में उन्होंने कुंती चरित्र, परीक्षित श्राप और कपिल–देवहूति संवाद का वर्णन करते हुए कहा कि श्रीमद्भागवत कथा का संकल्प मात्र भी मनुष्य के जीवन का उद्धार करने वाला है। उन्होंने कहा कि कलयुग में यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से सात दिनों तक श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण कर ले, तो उसे जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। कथा के समापन पर आरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान एवं आयोजक भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील कुमार उपाध्याय, पद्मावती उपाध्याय, सतीश उपाध्याय, नीलम उपाध्याय, शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार उपाध्याय, स्नेहलता उपाध्याय, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, पंकज मिश्र, पीयूष गुप्ता, अरुण उपाध्याय, ओमप्रकाश सिंह, कपिलमुनि मिश्र, रमाशंकर उपाध्याय, रामसागर शुक्ल, लालजी शुक्ल, लालप्रताप सिंह, नरेंद्र सिंह, सदानंद शुक्ल, कैलाश शुक्ल, हीरामणि उपाध्याय, जयशंकर पाल, संतोष शुक्ल, विकास, अभिषेक, पुजारी आदर्श मिश्र, अरविंद सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे।

## मंगेतर से मिलते ही छलक पड़े आंसू, आजाद बिंद हत्याकांड की दर्दभरी यादें फिर हुईं ताजा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में खेतासराय थाना अंतर्गत दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड में न्याय की लड़ाई लड़ रही सौम्या बिंद मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद मृतक की होने वाली दुल्हन सोनी बिंद के घर जमदहा (बीबीपुर) सोमवार को पहुंचीं। जैसे ही दोनों आमने–सामने हुईं, वे एक–दूसरे से लिपटकर फूट–फूटकर रो पड़ीं। यह भावुक दृश्य देखकर वहां मौजूद परिजनों और ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं तथा घर का माहौल गमगीन हो उठा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच गांव पहुंची सौम्या को देखकर मृतक के होने वाले ससुराल पक्ष के लोग भावुक हो गए। काफी देर तक सौम्या ने सोनी को ढांढस बंधाया और हिम्मत बनाए रखने की बात कही। मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को संभाला। इस दौरान सौम्या ने कहा कि मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई और न्याय का भरोसा मिला है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई के हत्यारों को सख्त सजा दिलाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगी। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़उर गांव निवासी आजाद बिंद की शादी

जमदहा (बीबीपुर) निवासी सोनी बिंद से तय थी। एक मई की रात बारात लेकर जाते समय शाहगंज–जौनपुर मार्ग पर बादशाही के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें आजाद बिंद की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे जनपद के साथ प्रदेशभर में आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर भोले राजभर, रवि यादव और प्रदीप बिंद के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। मामले का एक आरोपी रवि यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। इसी को लेकर परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं।और सौम्य बिंद उनके भी इनकाउंटर की माग कर रही है।

## कला, संस्कृति और संस्कारों का संगम बना संस्कार भारती का समापन समारोह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। संस्कार भारती जौनपुर द्वारा आयोजित 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का भव्य समापन नगर स्थित होली चाइल्ड एकेडमी में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यशाला में बच्चों को चित्रकला, कथक, लोकगीत, नाट्य कला एवं कंटेम्प्रेरी डांस का प्रशिक्षण दिया गया, जिसका शानदार प्रदर्शन प्रतिभागियों ने समापन समारोह में किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं नटराज प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉ. प्रमोद श्रीवास्तव, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ. अशोक सिंह रघुवंशी, संरक्षक रविन्द्र नाथ, काशी प्रांत महामंत्री सुजीत, कार्यकारिणी सदस्य ऋषि श्रीवास्तव, अध्यक्ष डॉ. ज्योति दास एवं महामंत्री अमित अंशु उपस्थित रहे। प्रशिक्षुओं द्वारा बनाई गई चित्रकला एवं आर्ट–क्राफ्ट प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं लोकगीत, कंटेम्प्रेरी डांस और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। कथक प्रशिक्षुओं ने सरस्वती वंदना, महिषासुर मर्दिनी और द्रौपदी चीरहरण प्रसंग की प्रभावशाली प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी (भू एवं राजस्व) अजय अम्बष्ट ने कहा कि मोबाइल के बढ़ते प्रभाव के बीच ऐसी कार्यशालाएं बच्चों के रचनात्मक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने संस्कार भारती के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। समापन अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र वितरित किए गए तथा पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यशाला में योगदान देने वाले सभी प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आलोक रंजन सिन्हा एवं मयंक नारायण ने संयुक्त रूप से किया। अंत में महामंत्री अमित अंशु ने सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं सहभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक वंदे मातरम् गायन के साथ हुआ।

## अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर 24 घंटे चला विरोध, मरम्मत और कार्रवाई के आश्वासन पर मामला शांत

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित बक्शा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार सातक जारी रहा। अधिकारियों के हस्तक्षेप और आवश्यक आश्वासनों के बाद मंगलवार को मामला शांत हो गया। ग्रामीणों के अनुसार रविवार रात अज्ञात लोगों द्वारा प्रतिमा पर पथराव किया गया, जिससे प्रतिमा के दाहिने हाथ की एक उंगली टूट गई। सोमवार शाम घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रतिमा स्थल पर एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीण नई प्रतिमा स्थापित करने तथा दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंची बक्शा पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए रात भर पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। मंगलवार सुबह सदर तहसीलदार महेंद्र कुमार भी घटनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। अधिकारियों ने प्रतिमा की मरम्मत, दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी तथा प्रतिमा स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। अधिकारियों की मौजूदगी में क्षतिग्रस्त प्रतिमा की मरम्मत कराई गई तथा प्रतिमा का जलाभिषेक, पूजा–अर्चना और माल्यार्पण किया गया। इस दौरान लोगों ने 'जय भीम' के नारे भी लगाए। थानाध्यक्ष लक्ष्मण विक्रम सिंह का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में बसारतपुर निवासी राजेश पाल पुत्र देवराज पाल के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

## प्रभारी डॉक्टर नहीं, फार्मासिस्ट की कुर्सी खाली- संविदा डॉक्टर लिख रहे बाहर की दवा

गोरखपुर, (संवाददाता)। खुखुंदू न्यू पीएचसी खुखुंदू में प्रभारी चिकित्साधिकारी का पद खाली है तो वहीं फार्मासिस्ट गायब मिले। उधर, बीएएमएस डाक्टर अपने कक्ष में बैठकर मरीज देख रहे थे। लेकिन वह भी अधिकतर दवा बाहर का लिख रहे थे। बताते चलें, देवरिया और सलेमपुर के बीच में स्थापित न्यू पीएचसी खुखुंदू बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां एमबीबीएस डाक्टर की तैनाती होने पर बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचते है। मगर दुर्भाग्य यह है कि यह पीएचसी विभागीय अधिकारियों की उदासीनता से महत्वहीन बनकर रह गया है। यहां कुछ दिन एमबीबीएस डाक्टर रहने के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिसके चलते लोगों को झोलाछाप डॉक्टरों के पास जाकर महंगा इलाज कराना पड़ता है। सोमवार दिन में करीब 11.20 पर अस्पताल पहुंचने पर फार्मासिस्ट की कुर्सी खाली पड़ी थी। इस दौरान करीब 26 मरीजों का इलाज किया गया था। डाक्टर जेपी मोर्या ने बताया कि बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जो दवा मौजूद है,वही दवा लिखी जा रही है। बाहरी दवा लिखने का आरोप बेबुनियाद है।

## पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार अस्थाना की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। कायस्थ कल्याण समिति, जौनपुर द्वारा समिति के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय प्रदीप कुमार अस्थाना की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नगर स्थित आर.के. पैलेस (मैहर मंदिर के निकट) के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोगों, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा समिति के सदस्यों ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने स्वर्गीय प्रदीप कुमार अस्थाना के सौम्य एवं मधुर व्यवहार, सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा समाज सेवा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद करते हुए उन्हें एक प्रेरणास्रोत व्यक्तित्व बताया। वक्ताओं ने कहा कि उनका जीवन समाज के लिए समर्पित रहा और उनके कार्य सदैव लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। श्रद्धांजलि सभा में उनके छोटे भाई सुनील अस्थाना सहित समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञान चन्द्र श्रीवास्तव, संस्थापक सदस्य कौशल कुमार अस्थाना, इंजीनियर आर. डी. श्रीवास्तव, संरक्षक प्रदीप

श्रीवास्तव, आनंद मोहन, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश महासचिव राकेश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव रवि श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष नीलमणि श्रीवास्तव, जिला महासचिव संजय अस्थाना,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पत्रकार विश्व प्रकाश श्रीवास्तव दीपक, भालेन्द्र श्रीवास्तव, आलोक रंजन सिन्हा, डॉ. संजय श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष दयाल शरण श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, सभासद पंकज श्रीवास्तव, अनिल अस्थाना, श्याम रतन श्रीवास्तव, अमित अस्थाना, अजय श्रीवास्तव, गिरवर अस्थाना, गिरिजेश श्रीवास्तव, अनूप सिन्हा, लालमोहन श्रीवास्तव, एस.सी. लाल, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, सुशील श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, विजय अस्थाना, विनोद अस्थाना सहित बड़ी संख्या में चित्रांश बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन समिति के महासचिव विपनेश कुमार श्रीवास्तव ने किया। अंत में सभी ने स्वर्गीय प्रदीप कुमार अस्थाना के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

## दाम बढ़ने से गृहिणियों और मध्यमवर्गीय परिवारों की बढ़ी चिंता

गोरखपुर, (संवाददाता)। घरेलू गैस सिलिंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी ने गृहिणियों, मध्यमवर्गीय परिवारों और छोटे स्तर पर काम करने वाली महिला उद्यमियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। रसोई का बजट संभालना पहले से ही कठिन हो रहा था, गैस की कीमतों में वृद्धि ने परिवारों के मासिक खर्च को और प्रभावित कर दिया है। महिलाओं का कहना है कि खाद्य सामग्री, सब्जियों, दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों के बीच अब रसोई गैस का महंगा होना अतिरिक्त बोझ साबित हो रहा है। गृहिणियों के अनुसार, परिवार की आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है जबकि रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में घरेलू बजट को संतुलित रखना चुनौती बन गया है। दूसरी ओर, घर से छोटे व्यवसाय संचालित करने वाली महिला उद्यमियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। टिफिन सेवा, घरेलू खाद्य उत्पाद, बेकरी आइटम और अन्य खाद्य व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि गैस की लागत बढ़ने से उत्पादन खर्च में वृद्धि हुई है। लगातार बढ़ती महंगाई का सबसे अधिक असर घर की रसोई पर दिखाई देता है क्योंकि परिवार के दैनिक खर्चों का प्रबंधन मुख्य रूप से गृहिणियों को ही करना पड़ता है। रसोई गैस के दाम बढ़ने से घर का पूरा बजट प्रभावित हो गया है। पहले से ही दाल और अन्य जरूरी सामान महंगे हैं। अब सिलिंडर महंगा होने से महीने के खर्चों को संभालना और मुश्किल हो गया है। रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है। पहले जहां महीने का बजट आसानी से बन जाता था, अब हर खर्च को सोच–समझकर करना पड़ रहा है। गैस के दाम बढ़ने से घरेलू महिलाओं की परेशानियां और बढ़ गई हैं। मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बढ़ती महंगाई बड़ी चिंता बन गई है। बच्चों की पढ़ाई, बिजली बिल और अन्य खर्चों के बीच गैस सिलिंडर महंगा होना अतिरिक्त बोझ है।

## अपार आईडी नहीं बनी तो स्कूलों पर होगी कार्रवाई

गोरखपुर, (संवाददाता)। जिले के सभी विद्यालयों में छात्रों की अपार आईडी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद अभी भी बहुत से निजी विद्यालय अपार आईडी बनाने में रूचि नही दिखा रहे हैं। अभी भी करीब 40 प्रतिशत छात्रों की अपार आईडी नहीं बन सकी है। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी विद्यालयों को 30 जून तक शत–प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अपार आईडी के माध्यम से प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या (पेन) प्रदान की जाती है। यह 11 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जो छात्र की पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान एक ही रहता है।

# शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु ग्राम पंचायतों में आयोजित हुई जन चौपाल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर "सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान के 12 वर्ष" थीम के अंतर्गत जनपद में समेकित जनकल्याण एवं जन–जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों को जन–जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में जन चौपाल, स्वच्छता अभियान, पौधरोपण, जनसंवाद तथा जनसमस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. के निर्देशों के क्रम में पंचायत राज विभाग द्वारा जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए इसके उपयोग को पूर्णतः बंद करने का संदेश दिया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन सिंह के नेतृत्व में संचालित सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन अभियान के अंतर्गत आज लगभग 40 कुंतल प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण किया गया। साथ ही सर्वाधिक अस्वच्छ सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित कर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। प्लास्टिक मुक्त तालाब अभियान के अंतर्गत विकास खंड बक्शा, ग्राम पंचायत बक्शा तथा विकास खंड सिकरारा की ग्राम पंचायत पालपुर में तालाबों के सौंदर्यीकरण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट मुक्त करने के कार्यों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जनपद में 08 जून से 14 जून 2026 तक संचालित "विशेष जन सम्पर्क एवं जन–जागरूकता अभियान" के अंतर्गत आज समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की गईं तथा मलिन बस्तियों में संवाद कार्यक्रम एवं जनसमस्या समाधान शिविर लगाए गए। इसी क्रम में "सरकार आपके द्वार" स्वरुप के अंतर्गत विकास खंड बदलापुर की ग्राम पंचायत मलूकपुर स्थित मलिन बस्ती में आयोजित जन चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। उपस्थित नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, उज्ज्वला योजना, मनरेगा तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों द्वारा आवास, शौचालय, विद्युत, पेंशन सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने, स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने तथा जनभागीदारी के माध्यम से विकास कार्यों में सहयोग करने का आह्वान किया गया।

# 'ऐंठापुर में ज्येष्ठ मास के छठे मंगल पर बंटा शीतल शरबत'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' ज्येष्ठ मास के छठे मंगलवार के पावन अवसर पर भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ऐंठा पुर में सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव एवं श्रद्धालुओं के सहयोग से पवित्र मास ज्येष्ठ के छठे मंगलवार पर शीतल शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व कार्यक्रम के संयोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम वीरों के वीर महावीर (बजरंग बली) के पावन चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर फल,मेवा मिष्ठान से भोग लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने विशाल स्टॉल लगाकर राहगीरों और भक्तों को शीतल शरबत पिलाया एवं बूंदी का परसाद वितरण किया। भीषण गर्मी में रोड से गुजरने वाले राहगीरों ने अपनी –अपनी गाड़ियों को रोककर श्रध्दापूर्वक शीतल शरबत एवं बूंदी का परसाद ग्रहण किया। भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच राहगीरों ने शीतल शरबत का सेवन कर अपनी प्यास बुझाई। अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बड़े मंगल पर बजरंग बली महाराज जी की सेवा और राहगीरों की प्यास बुझाने से जो आत्म संतुष्टि मिली वह अद्भुत है। इस पुनीत कार्य में अरविंद कुमार श्रीवास्तव, अनुज कुमार श्रीवास्तव सहित स्थानीय लोगों,महिलाओं, बच्चों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया और व्यवस्था संभालने में सक्रिय भूमिका निभाई।

# आईजीआरएस रैंकिंग में अयोध्या टाप टेन मे शामिल, हासिल किया चौथा स्थान

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। जनपद अयोध्या ने जनशिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए माह मई 2026 की आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम) रैंकिंग में प्रदेश स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है।वर्ष 2020 के बाद यह पहला अवसर है जब जनपद अयोध्या ने आईजीआरएस रैंकिंग में प्रदेश के टॉप–10 जनपदों में स्थान बनाया है।इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने समस्त प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता जनपद प्रशासन की जनहित के प्रति प्रतिबद्धता, पारदर्शी कार्यप्रणाली तथा शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त उपलब्धि को बनाए रखते हुए शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता में और अधिक सुधार किया जाए तथा प्रत्येक शिकायतकर्ता को संतुष्टिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई एवं शिकायत निवारण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाकर जनविश्वास को मजबूत किया जाएगा।

# बस यात्रियों की जान जोखिम मे डालकर विभिन्न रूटों पर संचालित हो रही जर्जर जनरथ बस

अयोध्या। इस प्रचंड गर्मी में अयोध्या आने व यहाँ से जाने वाले बस यात्रियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए अयोध्या बस स्टैंड सिविल लाइन से वाराणसी,प्रयागराज, कानपुर राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त संख्या में जनरथ,इलेक्ट्रिक एसी बसों का संचालन शुरु है।जिसमें से इस डिपो से संचालित इन रूटों पर चलने वाली जनरथ एसी बसें काफी पुरानी और जर्जर अवस्था में हो गई है। यह जनरथ एसी बसें यात्रा के दौरान कब कहां खड़ी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता।इसका जीता जागता उदाहरण मंगलवार को उस समय दोपहर मे दिखाई दिया। जब प्रयागराज डिपो अयोध्या बस स्टैंड सिविल लाइन से प्रयागराज को जनरल बस जा रही थी तभी सर्किट हाउस के समीप बिगड़ गई और वही बीच सड़क पर खड़ी हो गई।गनीमत यह रही कि यह बस रोडवेज बस स्टैंड के समीप ही खराब हुई नहीं तो इस भीषण गर्मी में यात्री कहां जाते।जनरथ एसी बस खराब होने की घटना आज की ही नहीं है बल्कि इसके पहले भी प्रयागराज को जाने वाली जनरथ एसी बस कभी बीकापुर के आसपास तो कभी प्रयागराज के अन्य स्थानों पर भी बिगड़ गई है और खड़ी हो गई है।जिसके चलते इस बस पर सवार बस यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।वहां पर तैनात रोडवेज कर्मियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यहां से संचालित अधिकतर चाहे जनरथ बसें हो या फिर सामान्य बसें हो उनमें से अधिकतर बसें अपनी आयु सीमा पूरी कर चुकी है लेकिन विभाग चालक परिचालक के साथ–साथ बस यात्रियों की जान जोखिम मे डालकर जर्जर जनरथ बसों का संचालन जबरन करा रही है।जिसके चलते आए दिन कहीं ना कहीं किसी जगह रोडवेज की बसें अचानक बिगड़ जाती है और वही खड़ी हो जाती हैं।रोडवेज कर्मियों की माने इस समय वाराणसी रूट पर वर्तमान समय में 8 जनरथ बसें प्रयागराज और बनारस मार्ग पर संचालित हैं।जबकि 11 आयशर एसी बसें जिनमें तीन कानपुर चार–चार बसें वाराणसी और प्रयागराज राजमार्ग पर चल रही है।देखा जाए तो इसी तरह 20 इलेक्ट्रनिक एसी बसों में से 8 बसे प्रयागराज लखनऊतथा गोंडा राजमार्ग पर भी चलाई जा रही हैं। इस संबंध में रोडवेज के एक कर्मचारी ने बताया उक्त बस में क्लच खराब हो गया था जिसे ठीक किया जा रहा है।

# दूसरे दिन पुलिस भर्ती परीक्षा मे 1889 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित

अयोध्या।दूसरे दिन मंगलवार को पुलिस भर्ती परीक्षा 12 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न हुई।जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर दोनों पालियों में आयोजित हुई परीक्षा में 10272 अभ्यार्थियों मे से 8383 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया।वही 1889 विद्यार्थी परीक्षा मे शामिल नहीं हुए।पहली पाली में कुल 5136 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4162 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए,जबकि 974 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।दूसरी पाली में कुल 5136 अभ्यर्थियों में से 4221 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 915 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे।केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ ही निगरानी व्यवस्था को मजबूत रखा गया। अभ्यर्थियों की पहचान और प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी कराई गई,परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए डीएम शशांक त्रिपाठी, एसएसपी डाक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य आला अधिकारी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए।

# केनरा बैंक अलीगंज शाखा में विशाल भंडारे का भव्य आयोजन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। केनरा बैंक अलीगंज शाखा द्वारा सामाजिक समरसता, सेवा एवं जनकल्याण की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) अवनीश कुमार सिंह द्वारा फीता काटकर एवं पूजा–अर्चना के साथ किया गया। इस अवसर पर केनरा बैंक लखनऊ अंचल कार्यालय के महाप्रबंधक (जीएम) अजित कुमार मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार चौधरी, सीनियर मैनेजर धनंजय सिंह, बैंक के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, ग्राहक तथा क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में एमएलसी श्री अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन समाज में आपसी भाईचारे, सहयोग एवं सद्भाव को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। उन्होंने केनरा बैंक द्वारा आयोजित इस भव्य भंडारे की सराहना करते हुए कहा कि बैंकिंग सेवाओं के साथ–साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाप्रबंधक श्री अजित कुमार मिश्रा ने कहा कि केनरा बैंक सदैव समाजहित एवं जनकल्याण से जुड़े कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाता रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन समाज के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करते रहेंगे। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, ग्राहकों एवं स्थानीय नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन स्थल पर श्रद्धा, सेवा और सामाजिक एकता का वातावरण बना रहा। सभी आगंतुकों के लिए प्रसाद एवं भोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम के अंत में शाखा प्रबंधक श्री प्रदीप कुमार चौधरी ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनसमुदाय का आभार व्यक्त किया। सीनियर मैनेजर श्री धनंजय सिंह ने आयोजन की सफलता में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से यह विशाल भंडारा सफलतापूर्वक एवं भव्य रूप से संपन्न हुआ, जिसकी उपस्थित जनों ने भूरि–भूरि प्रशंसा की।

# निपुण भारत मिशन का होगा विस्तार, अब कक्षा 5 तक मजबूत होगी बच्चों के सीखने की नींव

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा में सुधार के तहत निपुण भारत मिशन को अब कक्षा पांच तक करने की तैयारी है। इससे बच्चों की आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) को मजबूत किया जा सकेगा। इसके लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) विषयों के लिए नए अधिगम लक्ष्य और दक्षताएं तय की जा रही हैं। कार्ययोजना के अनुसार इन दक्षताओं और लक्ष्यों को

20 जून तक अंतिम रूप देकर अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। हाल में यह कार्ययोजना अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा के सामने प्रस्तुत की गई। बैठक में निपुण भारत मिशन के विस्तार कक्षा 3 से 5 तक करने, अधिगम लक्ष्यों के निर्धारण, शिक्षक परामर्श प्रक्रिया तथा क्रियान्वयन रणनीति की प्रगति की चर्चा की गई। इसी आधार पर रूपरेखा को आगे बढ़ाया जा रहा है।प्रदेश में अभी कक्षा 1 और दो में निपुण भारत मिशन चल रहा है। इसके माध्यम से बच्चों की सीखने की मजबूत बुनियाद की जा रही है। इसी क्रम में निपुण भारत मिशन का विस्तार कर कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने का प्रयास है।

# 'जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ परीक्षा केन्द्रों का किया निरीक्षण'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के साथ संयुक्त निरीक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 की प्रथम पाली की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत आर आर इण्टर कालेज नघेटा रोड तथा महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, शौचालय तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि परीक्षा को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु बनाए गए हेल्प डेस्क, प्रतीक्षा स्थल तथा सुरक्षा प्रबंधों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा अवधि में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए तथा संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखी जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं सजगता से करने के निर्देश दिए।

# सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने रचा सफलता का नया इतिहास

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती, आवश्यकता केवल सही अवसर, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की होती है। उत्तर प्रदेश सरकार की इसी सोच को साकार कर रहे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने इस वर्ष जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है।प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित इन आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उचित वातावरण उपलब्ध कराया जाए तो ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं।इस वर्ष सर्वोदय विद्यालयों के 11 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, जबकि छात्रा प्रीति ने जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इन उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। मिर्जापुर के मड़िहान स्थित सर्वोदय विद्यालय को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है, जहां विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन, नियमित टेस्ट, आधुनिक अध्ययन सामग्री एवं प्रतियोगी वातावरण ने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को नई दिशा दी है।इस वर्ष जेईई मेंस में सफल होने वाले विद्यार्थियों में मिर्जापुर की दामिनी पटेल, अंबाला वर्मा, सृष्टि, शिवानी और रागनी सहित कुल 11 विद्यार्थी शामिल हैं। वहीं देवरिया, बाराबंकी और बस्ती के विभिन्न सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी परीक्षा में सफलता अर्जित की है। विशेष रूप से प्रीति और दामिनी पटेल को आईआईटी मंडी के प्रतिष्ठित बीबीए एवं एमबीए कार्यक्रमों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो इस शैक्षिक मॉडल की सफलता को और अधिक सशक्त बनाता है।समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में वर्तमान में 103 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, पुस्तकें एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा प्रदान की जाती है।इन विद्यालयों का उद्देश्य केवल शैक्षणिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व निर्माण, खेलकूद एवं रचनात्मक गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

# खेड़ा राठौर वृहद गौ संरक्षण केंद्र बना ग्रामीण विकास और पशुधन प्रबंधन का आदर्श मॉडल

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में कृषि एवं पशुपालन सदैव आर्थिक और सामाजिक जीवन की धुरी रहे हैं। निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश की बढ़ती समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा लागू निराश्रित गोवंश संरक्षण कार्यक्रम अब प्रभावी परिणाम दे रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है।आगरा जनपद के बाह तहसील स्थित ग्राम खेड़ा राठौर में स्थापित वृहद गौ संरक्षण केंद्र इस नीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व स्थापित यह केंद्र आज बेसहारा, बीमार एवं कमजोर गोवंश के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में विकसित हो चुका है।चार सौ गोवंश की क्षमता वाले इस केंद्र में वर्तमान में चार सौ से अधिक पशु सुरक्षित रूप से संरक्षित हैं। जिला प्रशासन के कुशल प्रबंधन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलते प्रत्येक पशु को समुचित पोषण, चिकित्सा सुविधा एवं देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है।करीब एक एकड़ क्षेत्रफल में विकसित इस केंद्र में चार सौ कुंतल क्षमता वाला भूसा गोदाम, आधुनिक चरही व्यवस्था, केयरटेकर कक्ष एवं प्रशासनिक कार्यालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भूसा गोदाम का निर्माण उत्तरदृदक्षिण दिशा में किया गया है, जिससे वायु संचार एवं नमी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके और चारे की गुणवत्ता लंबे समय तक सुरक्षित रहे।केंद्र का स्थान चयन भी वैज्ञानिक आधार पर किया गया है, जो आबादी क्षेत्र से सुरक्षित दूरी पर स्थित होने के साथ ही मुख्य मार्ग से पक्की सड़क द्वारा जुड़ा है, जिससे चारे की आपूर्ति एवं चिकित्सकीय सेवाओं का संचालन सुचारू रहता है। बेहतर जल निकासी व्यवस्था के कारण बरसात के मौसम में भी परिसर जलभराव से मुक्त रहता है।यहां वर्तमान में बछड़े एवं बछड़ियों सहित गर्भवती और दुधारू गायों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लगभग दो टन प्रतिदिन हरे चारे का उत्पादन केंद्र परिसर में ही किया जा रहा है, जिससे यह आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है।इस योजना के परिणामस्वरूप न केवल गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिला है, बल्कि किसानों की फसलों को होने वाला नुकसान भी लगभग समाप्त हो गया है।

# 47 यात्रियों की क्षमता वाली बस में मिले 167 यात्री, इमरजेंसी गेट पर लगी थी बेंचे, लखनऊ में की गई सीज

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में जांच के दौरान बिहार से पंजाब जा रही स्लीपर बस में 167 यात्री मिले। जबकि, बस की क्षमता 47 यात्रियों की थी। परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने बस को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सीज कर दिया। यात्रियों को छतों पर भी बिठाया गया था। मामला स्लीपर बस संख्या यूपी 11 बीटी 0077 का है। यह बस बिहार के मुजफ्फरपुर से पंजाब के पटियाला के लिए जा रही थी। एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर डग्गेमार बसों की जांच कर रहे थे। इसी बीच टोल के पास स्लीपर बस आती हुई दिखाई दी, जिसकी छत पर ढेरों यात्री बैठे हुए थे। प्रवर्तन टीम ने बस को रुकवाया और जांच की। इसमें 167 यात्री पाए गए। कागजों की पड़ताल में बस का आल इंडिया परमिट भी समाप्त पाया गया। बस में यात्रियों की स्वीकृत क्षमता 47 यात्रियों की थी। यात्रियों को उतारकर बस सीज कर दी गई। सूत्रों ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जहां कार्रवाई हुई है, वहीं पर परिवहन विभाग के दो इंटरसेप्टर भी खड़े थे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।